जे + समुइल वगै0

बनाम

गट्टु महेश वगै0

सिविल अपील नंबर 561@2012

जनवरी 16 2012

पी + सदाशिवम और जे + चेलमेश्वर] जे +जे +

302 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय पी- सदाशिवम, जे- द्वारा सुनाया गया। 1- छुट्टी स्वीकृत।

2- यह अपील सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 5162@2010 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद द्वारा पारित दिनांक 08-02-2011 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसके तहत उच्च न्यायालय ने दिनांकित आदेश को रद्द करते हुए द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 20-10-2010 पारित किया गया। करीमनगर जगतियाल ने यहां उत्तरदाताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया।

3- संक्षिप्त तथ्यः

करीमनगर के सूबा को 12-03-1978 को दोर्नाकल के इसके मूल सूबा से शामिल किया गया था। 22-08-1985 को सेवानिवृत्त डायोसेसन

कोषाध्यक्ष और संपत्ति सचिव, करीमनगर ने एसी को स्वीकार करते हुए सर्वेक्षण संख्या 43 वाली भूमि की नीलामी के लिए अखबार में एक प्रकाशन जारी किया। 3-31 ग्राम- मिशन कंपाउंड धर्मपुरी रोड जगतियाल में स्थित है और निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 05-09-1985 निर्धारित की गई थी। 13-09-1985 को सीलबंद निविदाएं खोली गईं। और यहां गट्टू महेश-प्रतिवादी नंबर 1 और यहां कोठा मोहन-प्रतिवादी नंबर 2 मेसर्स जगत स्वप्ना एंड कंपनी में मैनेजिंग पार्टनर्स ने रुपये की राशि के लिए निविदाएं डालीं। 2455569@& रुपये की राशि के डीडी के साथ, जो ईएमडी का 10 izfr'kr है। सबसे अधिक बोली लगाने वाले होने के कारण उनकी निविदाएं स्वीकार कर ली गईं।

संपत्ति की बिक्री का अनुबंध 27-09-1985 को करीमनगर सूबा के साथ प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के बीच दर्ज किया गया था। अनुबंध में यह उल्लेख किया गया था कि करीमनगर सूबा रुपये प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ। 250000@& 08-11-1985 को या उससे पहले क्योंकि बिक्री के तहत भूमि एफ विवाद के तहत थी और शेष राशि का भुगतान नगर पालिका, जगतियाल द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को अंतिम रूप देने और मंजूरी मिलने के बाद ही उत्तरदाताओं द्वारा किया जाना था। नगर पालिका, जगतियाल द्वारा लेआउट। 03-04-2003 को, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने करीमनगर सूबा को एक कानूनी नोटिस जारी किया जिसमें बताया गया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही 05-05-1986 को हटा दी गई थी और

नगर पालिका] जगतियाल द्वारा लेआउट की मंजूरी 28-12-1989 को पूरी हो गई थी और निष्पादित करने के लिए और अनुबंध दिनांक 27-09-1985 के अनुसार उनके पक्ष में विक्रय विलेख पंजीकृत करें।

जे- सैमुअल और अन्य बनाम गट्टू महेश और अन्य। पी सदाशिवम] जे-

करीमनगर सूबा से पर्याप्त प्रतिक्रिया के अभाव में, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने ओ-एस- दायर किया। बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए जगतियाल में द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करीमनगर की अदालत में 2004 की संख्या 9। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, करीमनगर सूबा ने अंतर्निहित दोषों को इंगित करते हुए लिखित बयान दायर किया, अर्थात् विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16 (सी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के फॉर्म 47, परिशिष्ट 'ए' की अनिवार्य आवश्यकताओं की अनुपस्थिति। 24-09-2010 को, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने आई-ए- दायर किया। ओएस में 2010 की संख्या 1078 संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत 2004 की संख्या 9 में विशिष्ट राहत अधिनियम और संहिता की उपरोक्त धारा के अनुपालन में विशिष्ट दलील को शामिल करने के लिए याचिका में संशोधन की मांग की गई है, इस आधार पर कि यह टाइपोग्राफिक त्रुटि के कारण छूट गया था। 04-10-2010 को

करीमनगर सूबा ने आवेदन का विरोध करते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया।

आदेश दिनांक 20-10-2010 द्वारा, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर संशोधन के आवेदन को खारिज कर दिया। आदेश से व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने 2010 की सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 5162 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 08-02-2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा मांगे गए संशोधन की अनुमति दी।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर उत्तरदाताओं ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी है।

4- अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील श्री ए- सुब्बा राव और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील श्री के- स्वामी को सुना।

5- इस अपील में विचार करने का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या उच्च न्यायालय मुकदमे के समापन के बाद दायर की गई याचिका में संशोधन के लिए आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत दायर आवेदन को अनुमति देने और मामले को आदेश के लिए आरक्षित करने में सही है।

6- दिनांक 27-07-1985 के समझौते के आधार पर, जो जगतियाल में मिशन कंपाउंड धर्मपुरी रोड में स्थित सर्वेक्षण संख्या 43 में 3 एकड़ और 31 गुंठा भूमि की बिक्री से संबंधित है, 2455569@& रुपये पर

उत्तरदाताओं ने /वादी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए उक्त मुकदमा दायर किया। चूंकि हमने पहले ही तथ्यात्मक विवरण का उल्लेख किया है, इसलिए आदेश 6 नियम 17 के तहत दायर याचिका से संबंधित विवरण को छोड़कर इसे संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिस्पर्धी प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और दोनों पक्षों ने स्वीकार किया उनकी ओर से साक्ष्य और दोनों पक्षों की ओर से दलीलें 22-09-2010 को सुनी और पूरी की गईं। उस दिन कोर्ट ने मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था. इस बीच, 24-09-2010 को उत्तरदाताओं ने एक याचिका दायर कर वाद में संशोधन की प्रार्थना की। उक्त आवेदन के समर्थन में वादी नंबर 2 ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि वाद के पैरा 11 में उन्होंने बिक्री के समझौते दिनांक 27-09-1985 के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवादी नंबर 1 से 7 को 03-04-2003 को जारी किए गए कानूनी नोटिस के बारे में बताया है। 27-09-1985 और इसका कोई उत्तर नहीं मिला। शपथ पत्र के पैरा 3 में अभिसाक्षी ने कहा है कि प्रकार की गलती से निम्नलिखित वाक्य छूट गए हैं। वाद पत्र के पैरा 11 के बाद निम्नलिखित पैरा 12 भी जोड़ा जा सकता है।" 27-09-1985 के बिक्री समझौते को निष्पादित करने के लिए विशेष रूप से तैयार हैं और अभी भी तैयार हैं और इच्छुक हैं, जिस पर प्रतिवादियों ने ध्यान दिया है। मैं दिनांक 27-09-1985 के बिक्री समझौते के अनुसार शेष राशि के साथ तैयार हूं। मैं

प्रस्तुत करता हूं कि शिकायत के पैरा संख्या 12-18 को 13 से 19 के रूप में बदला जा सकता है।" वादी द्वारा उपरोक्त कथन में संशोधन और शामिल करने की प्रार्थना करने वाला एकमात्र कारण "प्रकार की गलती" है। यह भी कहा गया है कि यह उनके उचित परिश्रम के बावजूद हुआ।

7- उपरोक्त दावे का अपीलकर्ताओं ने विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर करके विरोध किया था। वादी के दावे की योग्यता पर विवाद करने के अलावा, आदेश 6 नियम 17 के तहत याचिका के संबंध में उन्होंने विशेष रूप से कहा कि लंबे मुकदमे में कई चरणों को पार करने के बाद, अंतिम मुकदमे में वादी की दलीलें 20-09-2010 को सुनी गईं। प्रतिवादियों ने 22-09-2010 को अपनी लिखित दलीलें भी दायर कीं, जिसमें वादी के अंतर्निहित दोष यानी सीपीसी की धारा 16 सी स्पष्टीकरण पप और फॉर्म 47 परिशिष्ट ए की अनिवार्य आवश्यकताओं की अनुपस्थिति को इंगित किया गया था। इसके बाद भी दोनों पक्षों की ओर से आगे बहस की गई और वादी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि अब और समय की आवश्यकता नहीं है और मामले को फैसले के लिए पोस्ट किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने मामले को निर्णय के लिए 04-10-2010 को पोस्ट कर दिया। केवल इस समय यानी 24-09-2010 को] वादी विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16 सी और परिशिष्ट ए सीपीसी के फॉर्म 47 के अनुपालन में विशिष्ट दलील को शामिल करने के लिए संशोधन की मांग करने वाली वर्तमान याचिका लेकर आए, इस आधार

पर कि वही था उचित परिश्रम के बावजूद "टाइप मिस्टेक" के कारण छूट गया। यद्यपि उक्त दावा ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार्य नहीं था, उच्च न्यायालय ने वादी को प्रार्थना के अनुसार वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति दी।

8- उच्च न्यायालय के तर्क की स्वीकार्यता या अन्यथा पर विचार करने से पहले, आदेश टप् नियम 17 सीपीसी का संदर्भ लेना उपयोगी है।

17- अभिवचनों में संशोधन- न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्ष को अपनी अभिवचनों में ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति दे सकता है जो उचित हों, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं पार्टियों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करना।

बशर्ते कि सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पार्टी सुनवाई शुरू होने से पहले मामला नहीं उठा सकती थी।''

उक्त प्रावधान को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा हटा दिया गया था। संशोधन अधिनियम की धारा 16 इस प्रकार हैः

16- आदेश 6 का संशोधन- प्रथम अनुसूची में, आदेश 6 में-

नियम 17 और 18 हटा दिये जायेंगे।"

वादियों और बार के सदस्यों के कड़े प्रतिरोध के बाद आदेश 5 नियम 17 को उसमें जोड़े गए प्रावधान के साथ फिर से पेश किया गया। उक्त प्रावधान के अनुसार, परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, उक्त नियम का एक अपवाद है अर्थात, यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्ष परीक्षण शुरू होने से पहले मामला नहीं उठा सकता है, तो संशोधन के लिए ऐसे आवेदन की अनुमति दी जा सकती है।

9- आगे बढ़ने से पहले] विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16 सी को देखना भी उपयोगी है जो इस प्रकार हैः

16- राहत के लिए व्यक्तिगत बाधाएँ- किसी अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन किसी व्यक्ति के पक्ष में लागू नहीं किया जा सकता-

जो यह कहने और साबित करने में विफल रहता है कि उसने अनुबंध की आवश्यक शर्तों का पालन किया है या करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक रहा है, जिन्हें उसके द्वारा पूरा किया जाना है, उन शर्तों के अलावा जिनके प्रदर्शन को रोका या माफ कर दिया गया है प्रतिवादी-

स्पष्टीकरण- खंड सी के प्रयोजनों के लिए-

जहां किसी अनुबंध में पैसे का भुगतान शामिल है, वादी के लिए वास्तव में प्रतिवादी को निविदा देना या अदालत में कोई पैसा जमा करना आवश्यक नहीं है, सिवाय इसके कि जब अदालत ने ऐसा निर्देश दिया हो;

वादी को प्रदर्शन, या तत्परता का ध्यान रखना चाहिए प्रदर्शन करने की इच्छा, अनुबंध अपने वास्तविक निर्माण के अनुसार।"

यह स्पष्ट है कि एक अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमे में। जब तक कोई विशिष्ट कथन न हो कि उसने अनुबंध की आवश्यक शर्तों का पालन किया है या करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक है, उसके द्वारा दायर किया गया मुकदमा खारिज किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त दावे के अभाव में कि वह अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक है, विशिष्ट निष्पादन के लिए न्यायालय द्वारा डिक्री नहीं दी जा सकती है।

10- इस कानूनी पृष्ठभूमि में, हमें एक बार फिर तथ्यात्मक विवरण दोहराना होगा। मौजूदा मामले में, सूट ओ-एस- लंबी सुनवाई के बाद 2004 का नंबर 9 सितंबर] 2010 में समाप्त हुआ। आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत संशोधन के लिए आवेदन 24-09-2010 को दायर किया गया था, यानी 22-09-2010 को बहस समाप्त होने के बाद और मामले को पोस्ट कर दिया गया था। 04-10-2010 को निर्णय हमने पहले ही उल्लेख किया है कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16 सी इस बात पर विचार करती है कि वादपत्र में विशिष्ट कथन किए जाने चाहिए जिन्हें उसने पूरा किया है और अधिनियम की आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहा है जिन्हें उसके द्वारा पूरा किया जाना है। यह धारा 16 सी का एक

आवश्यक घटक है और प्रपत्र उचित प्रदर्शन के लिए निर्धारित करता है। नियम 17 में डाले गए प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुकदमा शुरू होने के बाद किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि जब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उचित परिश्रम के बावजूद पक्ष मुकदमा शुरू होने से पहले मामला नहीं उठा सकता था।

11- जैसा कि पहले कहा गया है] वर्तमान मामले में, बहस पूरी होने के बाद संशोधन आवेदन 24-09-2010 को ही दायर किया गया था और मामला 04-10-2010 को निर्णय के लिए पोस्ट किया गया था। आदेश टप् के नियम 17 के परंतुक की उचित व्याख्या पर, पक्ष को न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि वह उस आधार की खोज नहीं कर सका जिसकी वकालत की गई थी। उचित परिश्रम के बावजूद, संशोधन द्वारा। निस्संदेह, नियम 17 अदालत को कार्यवाही के किसी भी चरण में दलीलों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। हालाँकि, मुकदमा शुरू होने के बाद प्रावधान उस शक्ति को प्रतिबंधित कर देता है। जब तक न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि संशोधन की अनुमति देने का कोई उचित कारण है, आम तौर पर न्यायालय को ऐसे अनुरोध को अस्वीकार करना पड़ता है। एक तर्क दिया गया कि चूंकि मुकदमा दायर करने से पहले भेजे गए कानूनी नोटिस में तत्परता और इच्छा का संदर्भ है और वादी ने साक्ष्य भी पेश किया है, इसलिए अदालत को उक्त आवेदन पर विचार करने से कोई नहीं रोकता है, जिसे हम स्वीकार करने में असमर्थ हैं। विशिष्ट राहत

अधिनियम की धारा 16(सी) के साथ-साथ आदेश 6 नियम 17 के परंतुक का प्रकाश। हलफनामे के रूप में ऐसा बताया गया एकमात्र कारण "प्रकार की गलती से चूक है। बेशक, किसी शब्द या अंकगणितीय संख्या का उल्लेख करना कोई भूल नहीं है। यह चूक विशिष्ट याचिका के संदर्भ में है जो विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16 (सी) के संदर्भ में अनिवार्य है।

12- न्यायालय का प्राथमिक उद्देश्य मामले की गुणवत्ता के आधार पर सुनवाई करना और यह सुनिश्चित करना है कि न्याय का शासन कायम रहे। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि मामले के सही तथ्यों को अदालत के सामने रखा जाए ताकि अदालत को अपने फैसले पर पहुंचने में सभी प्रासंगिक जानकारी मिल सके। इसलिए, कभी-कभी पार्टियों को अपने वादपत्रों में संशोधन करने की अनुमति देना आवश्यक होता है। किसी पक्ष को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति देने का न्यायालय का विवेक दो शर्तों पर आधारित है, पहला, दूसरे पक्ष के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए और दूसरा, पार्टियों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से संशोधन आवश्यक होना चाहिए। हालाँकि न्याय करने के प्रयास में पक्षों के हितों को संतुलित करने के लिए, परंतुक जोड़ा गया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है किः परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के

बावजूद, पार्टी मुकदमा शुरू होने से पहले इस मामले को नहीं उठा सकती थी।

13- उचित परिश्रम का विचार यह है कि कुछ प्रकार की राहत का अनुरोध करने से पहले उचित जांच आवश्यक है। विधिवत प्रत्याशित राहत प्राप्त करने के लिए न्यायिक तंत्र का उपयोग करने की इच्छा रखने वाले पक्ष के लिए मेहनती प्रयास एक आवश्यकता है। किसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को यह निर्धारित करने के लिए उचित परिश्रम करना चाहिए कि किए गए अभ्यावेदन तथ्यात्मक रूप से सटीक और पर्याप्त हैं। 'उचित परिश्रम' शब्द का उपयोग विशेष रूप से संहिता में किया जाता है ताकि यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण प्रदान किया जा सके कि परीक्षण शुरू होने के बाद अनुरोधित संशोधन की स्थितियों में विवेक का प्रयोग किया जाए या नहीं।

14- किसी दावे से उत्पन्न राहत का अनुरोध करने वाले पक्ष को उचित परिश्रम करने की आवश्यकता होती है और यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। शब्द "उचित परिश्रम" किसी पक्ष के रचनात्मक ज्ञान दावे के दायरे को निर्धारित करता है और मुकदमे के परिणाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

15- दिए गए तथ्यों में 'उचित परिश्रम' की स्पष्ट कमी है और की गई गलती निश्चित रूप से मुद्रण संबंधी त्रुटि के पूर्वावलोकन में नहीं आती

है। मुद्रण त्रुटि शब्द को मुद्रण/टाइपिंग प्रक्रिया के दौरान मुद्रित@टाइप की गई सामग्री में की गई गलती के रूप में परिभाषित किया गया है। इस शब्द में यांत्रिक विफलता या हाथ या उंगली के फिसलने के कारण होने वाली त्रुटियां शामिल हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें अज्ञानता की त्रुटियां शामिल नहीं हैं। इसलिए जिस कार्य को करना किसी का दायित्व है, उसे करने में लापरवाही बरतने को मुद्रण संबंधी त्रुटि नहीं कहा जा सकता। परिणामस्वरूप, इस संबंध में मुद्रण संबंधी त्रुटि की दलील पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थिति उचित परिश्रम की कमी की है, जिसमें इस तरह के संशोधन को संहिता के तहत निहित रूप से वर्जित किया गया है।

16- मुद्रण संबंधी त्रुटि/गलती का दावा निराधार है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में, जिस व्यक्ति ने वादपत्र तैयार किया, उस पर हस्ताक्षर किए और उसका सत्यापन किया, यदि उसने थोड़ा ध्यान दिया होता तो इस चूक को देखा जा सकता था और वहीं सुधारा जा सकता था। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि उचित परिश्रम का पालन किया गया था और किसी भी घटना में, 3 से 4 वाक्यों में चलने वाली अनिवार्य आवश्यकता की चूक एक टाइपोग्राफिक त्रुटि नहीं हो सकती है जैसा कि वादी द्वारा दावा किया गया है। परीक्षण द्वारा इन सभी पहलुओं पर सही ढंग से विचार किया गया है और निष्कर्ष निकाला गया है। अदालत और उच्च न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने में गलती की है कि यह उल्लेख करने में एक टाइपोग्राफिक त्रुटि थी और यह

एक आकस्मिक पर्ची थी। हालाँकि अपीलकर्ताओं के वकील ने कई निर्णयों का हवाला दिया है, लेकिन अध्ययन करने पर हमारा मानना है कि उनमें से कुछ मामलों का निर्णय आदेश टप् नियम 17 को प्रावधान के साथ शामिल करने से पहले या उस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर किया गया है। इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इस शक्ति को बरकरार रखा कि योग्य मामलों में, न्यायालय दूसरे पक्ष को लागत देकर क्षतिपूर्ति करके विलंबित संशोधन की अनुमति दे सकता है। 2002 में पेश किए गए आदेश टप् नियम 17 में संशोधन का पूरा उद्देश्य परीक्षण शुरू होने के बाद किसी याचिका में संशोधन के लिए आवेदन दाखिल करना रोकना है, ताकि आश्चर्य से बचा जा सके और पार्टियों को दूसरे के मामले की पर्याप्त जानकारी हो। यह आवेदन दाखिल करने में होने वाली देरी को रोकने में भी मदद करता है। (एनीग्लासे योहन्नान बनाम रामलता और अन्य, ¼2005½ 7 एससीसी 534] अजेंद्रप्रसादजी एन- पांडे और अन्य बनाम स्वामी केशवप्रकाशदासजी एन- और अन्य चंदर कांता बंसल बनाम राजिंदर सिंह आनंद, ¼2008½ 5 एससीसी 117] राजकुमार गुरुवार्ड ¼ मृत ½ एलआरएस के माध्यम से बनाम एस-के-सरवागी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य] ¼2008½ 14 एससीसी 364] विद्याबाई और अन्य बनाम पद्मलता और अन्य] ¼2009½ 2 एससीसी 409] मान कौर ¼ मृत ½ एलआरएस बनाम हरतार सिंह संघा द्वारा] ¼2010½ 10 एससीसी 512-

17- उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हैं और उच्च न्यायालय के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। तदनुसार, सिविल पुनरीक्षण याचिका में आदेश दिनांक 08-02-2011 पारित किया गया] क्रमांक 5162 को अलग रखा गया है।

18- लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के सिविल अपील की अनुमति है।

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कुमार मोहन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।